नवसर्जन संस्कृति

TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 225
दि. 16.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म 'स्पर्श' पर 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगी पंजीकृत हुए

पुराने विवादों के 94.3 प्रतिशत मामले सुलझा लिए गए; शिकायतों के निवारण का औसत समय 56 दिनों से घटकर 17 दिन हो गया

(जीएनएस)।

सही समय पर सही पेंशनभोगी को सही पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन प्रशासन प्रणाली – रक्षा (स्पर्श), जो डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है, देश का पहला संपूर्ण डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। प्रयागराज स्थित पीसीडीए (पेंशन) के माध्यम से रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा संचालित 'स्पर्श' ने नवंबर, 2025 तक भारत और नेपाल में 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगियों को अपने साथ जोड़ा है। यह 45 हजार से अधिक एजेंसियों द्वारा पहले प्रबंधित खंडित प्रणाली को एक एकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल ढांचे से प्रतिस्थापित करता है।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

पुराने सिस्टम से संबंधित 94.3 प्रतिशत विसंगतिपूर्ण मामलों का समाधान हो गया है : पिछली प्रणाली से स्थानांतरित किए गए 6.43 लाख विसंगतिपूर्ण मामलों में से 6.07 लाख मामलों को पेंशनभोगियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना सामान्य कर दिया गया है।

बुजुर्गों और तकनीकी रूप से कम जानकार पेंशनभोगियों के लिए व्यापक पहुंच : देश में 284 'स्पर्श' पहुंच कार्यक्रम और 194 रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान 8 हजार से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बढ़ी हुई पारदर्शिता और शिकायत निवारण : पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और आसानी से सुधार संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निवारण का औसत समय अप्रैल, 2025 में 56 दिन से घटकर नवंबर, 2025 में 17 दिन हो गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रक्षा लेखा विभाग ने 73 प्रतिशत संतुष्टि अंक प्राप्त किया है जिससे यह मंत्रालयों/विभागों में 5 वें स्थान पर है।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र 4.0 अभियान : रक्षा एवं पेंशनभोगी विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) 4.0 अभियान (1-30 नवंबर, 2025) के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग ने 202 कार्यालयों, 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और 15 भागीदार बैंकों को सक्रिय किया है जिन्हें 27 नोडल अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। 30 नवंबर, 2025 तक रक्षा

पेंशनभोगियों के लिए 20.94 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है।

वितरण : वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा पेंशन बजट के अंतर्गत 1,57,681 करोड़ रुपये का वितरण 'स्पर्श' के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर किया गया। जुलाई, 2024 में लागू वन रैंक वन पेंशन-III के अंतर्गत मात्र 15 दिनों में 20.17 लाख लाभार्थियों को 1,224.76 करोड़ रुपये का त्वरित वितरण संभव हुआ।

'स्पर्श' देश की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है और रक्षा कर्मियों के लिए एकमात्र पूर्णतः एकीकृत डिजिटल पेंशन समाधान है। यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मान, देखभाल और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का बयान

(जीएनएस)।

आज, मैं हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन के, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया और सल्तनत ऑफ ओमान की तीन देशों की यात्रा पर जा रहा हूं, ये तीनों ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के व्यापक समकालीन द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पुराने सभ्यतागत संबंध हैं।

सबसे पहले, मैं महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन जाऊंगा। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का प्रतीक होगी। अपनी यात्रा के दौरान, मैं महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जाफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करूंगा और महामहिम क्राउन प्रिंस अल

हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी मुलाकात करूंगा। अम्मान में, मैं जीवंत भारतीय समुदाय से भी मिलूंगा, जिन्होंने भारत-जॉर्डन संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अम्मान से, इथियोपिया के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर, मैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा करूंगा। अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अदीस अबाबा में, मैं महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के साथ विस्तार से बातचीत करूंगा और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा।

यूपीः सीएम योगी का नेहरू पर हमला- कहा देश में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ में हैं पूर्व पीएम

लखनऊ, (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को इतना विवादित करने का कार्य किया कि आजादी के बाद से वह लगातार भारत को डसता रहा। पंडित नेहरू के कारण उसी कश्मीर से देश को उग्रवाद, अलगाववाद प्राप्त हुआ था। देश पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी है, जिन्होंने लौहपुरुष व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए धारा-370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया।

योगी सोमवार को जीपीओ स्थित पार्क में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे समय तक प्राप्त होता, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। आजादी के बाद सरदार पटेल की सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद की रिसायतें भारत का हिस्सा बनीं।

सरदार पटेल ने गृहमंत्री के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार, तमाम विवादों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करने और भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य भी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी महेंद्र सिंह, अवनीश सिंह, पवन सिंह चौहान, लालजी प्रसाद निर्मल, उमेश द्विवेदी, विधायक ओपी श्रीवास्तव, आशीष सिंह 'आशु', भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सरदार पटेल स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष राजेश्वरी देवी पटेल, महासचिव शशांक वर्मा आदि मौजूद रहे।

तीन देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (15 दिसंबर, 2025) राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में ईरान, ब्रुनेई दारुस्सलाम और माइक्रोनेशिया के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए।

1 इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत, डॉ. मोहम्मद फथली

2. ब्रुनेई दारुस्सलाम की उच्चायुक्त, श्रीमती सिटी अरनीफरिजा हाजी मोहम्मद जैनी

3. माइक्रोनेशिया संघीय राज्यों के राजदूत, श्री जॉन फ्रिट्ज

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, मुंबईकरों के सस्ते घर का सपना अब होगा पूरा

(जीएनएस)।

नवी मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में घर खरीदना आज भी मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा सपना है। आय का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी को किराये में खर्च करने पड़ते है। अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऐलान से अपने घर का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नवी मुंबई में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (उकऊड) के आवास अब पहले से सस्ते हो गए हैं।

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि उकऊड के घरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इस फैसले से खासतौर पर आम आदमी, लो-इनकम और मिडिल-इनकम ग्रुप को बड़ा फायदा मिलने वाला है।

सस्ते आवास का सपना अब होगा पूरा

– नवी मुंबई पहले से ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और सुनियोजित विकास के लिए जानी जाती है।

– शहर में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरूआत भी हो चुकी है।

– यही वजह है कि यहां घर खरीदने की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो अब तक बढ़ती कीमतों की वजह से घर नहीं खरीद पा रहे थे।

मुंबईकरों को खुशखबरी

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि नवी मुंबई के विभिन्न नोड्स में उकऊड द्वारा बनाए गए आवासों की दरों में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इससे सरकारी आवास योजनाओं के तहत मिलने वाले घर अब और किफायती हो जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के इस फैसले का असर खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एहर) और निम्न आय वर्ग (छक्क्ष्) के लोगों को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि खारघर, वाशी, खारकोपर, तलोजा, उल्वे, कलंबोली, कामोठे और पनवेल जैसे इलाकों में उकऊड ने करीब 17 हजार घरों का निर्माण किया है।

लॉटरी के जरिए होगी घरों की बिक्री

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन घरों की लॉटरी प्रक्रिया अगले दो महीनों में पूरी की जाएगी। लॉटरी से पहले ही कीमतें घटाने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सभी के लिए आवास' अभियान को मजबूती देने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता के घर उपलब्ध कराए जाएं।

उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, देश की एकता और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रियासतों के एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं की नींव रखने में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के अमूल्य योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल के नेतृत्व में विशाल भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता वाले राष्ट्र को एकजुट करने की विकट चुनौती का सामना किया गया। यह उपलब्धि विश्ˆ व में भी किए गए तुलनीय प्रयासों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की शाश्वत विरासत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण को प्रेरित करती है(

नौसेना प्रमुख की ब्राजील यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिली

भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने 09 से 12 दिसंबर 2025 तक ब्राजील का अपना आधिकारिक दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों

देशों के बीच समुद्री साझेदारी को और अधिक मजबूत करना था।

यात्रा के दौरान, नौसेना प्रमुख ने ब्राजील के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें रक्षा मंत्री, ब्राजील सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ प्रमुख, और ब्राजील की

राजस्थान वाले हो जाएं सावधान! अब हड्डियों में घुसने वाली ठंड का दौर हो गया शुरू

(जीएनएस)।

पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चल सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर समेत दूसरे शहरों उदयपुर, जोधपुर में ठंड का असर दिख रहा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है।

मौसम विभाग ने अलवर, श्रीगंगानगर, जयपुर और जैसलमेर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को खासतौर पर सुबह और देर रात यात्रा करते समय कम गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में बढ़ेगी ठिठुरन

– बीते कुछ दिनों से राजस्थान में सर्दी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ठिठुरन और तेज होने की संभावना है।

– मौसम विभाग ने 11 से 16 दिसंबर के दौरान राज्य के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।

– नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कुछ जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है।

शेखावटी में येलो अलर्ट जारी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देशन में 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) की पहल

■ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जीपीआई की समीक्षा बैठक

गांधीनगर, 15 दिसंबर : सरकार के विभिन्न विभाग राज्य के नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नागरिक केंद्रित योजनाओं, सेवाओं, विकासोन्मुखी कार्यों, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तथा शिकायत निवारण के कामकाज से करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में इस उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अलग अलग प्रकार के कामकाज के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को 'सीएम डैशबोर्ड' पर एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाया गया है।

देश में सुशासन के रोल मॉडल के रूप में स्थापित गुजरात में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का दृष्टिकोण सुनिश्चित हो तथा योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह

'सीएम डैशबोर्ड' कार्यरत किया गया है।

टेक्नोलॉजी के समुचित उपयोग की पहलरूपी में यह 'सीएम डैशबोर्ड' देश के अन्य राज्यों के लिए जन हितोन्मुखी व योजनागत कार्यों के मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन के लिए एक उदाहरणरूपी प्लेटफॉर्म बना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुड गवर्नेंस की इस उज्ज्वल परंपरा को गतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से समग्रोन्मुखी गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) तैयार करवाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस जीपीआई के संदर्भ में गांधीनगर में विभागों की कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री श्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड, सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष श्री मुकेश पुरी, कृषि, ऊर्जा, नर्मदा जल संसाधन विभागों के अपर मुख्य सचिव, आदिजाति, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया तथा अन्य संबंधित विभागों के सचिव भी सहभागी हुए।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गाजियाबाद और नोएडा की वायु प्रदूषण कार्य योजनाओं की उच्च-स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की

दिल्ली-एनसीआर के लिए आगामी समीक्षा बैठकों की श्रृंखला

श्री भूपेंद्र यादव ने वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन का आह्वान किया और अनुपालन न करने पर शून्य सहनशीलता का निर्देश दिया

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के विरूद्ध लड़ाई जीतने की कुंजी के रूप में जन भागीदारी पर जोर दिया गया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एनसीआर में शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं पर समीक्षा बैठकों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में यह पहली समीक्षा थी, जिसका समापन आने वाले दिनों में राज्य-स्तरीय समीक्षा के साथ होगा। यह समीक्षा निर्धारित प्रारूप में की जा रही है, जैसा कि भूपेंद्र यादव ने 3 दिसंबर, 2025 को हुई पिछली समीक्षा बैठक में कहा था ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को बेहतर किया जा सके।

दोनों शहरों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा निम्नलिखित प्रमुख मापदंडों के आधार पर की गई:

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना;

औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का अनुपालन;

वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्थिति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता;

संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और पार्किंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना; निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)/पुराने अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए ढांचागत संवर्धन; धूल को कम करने के लिए सड़कों का पूर्णतः पक्कीकरण/टाइलिंग करना; यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएम) की तैनाती और एंटी-स्मॉग गन/वॉटर स्प्रिंकलर के उपयोग की स्थिति; पगडंडियों और खुले क्षेत्रों को हरा-भरा करना; जन भागीदारी पहल जिसमें सूचना एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां और ऐप आधारित शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।

मंत्री महोदय ने शेष औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थापना के लिए किए जा रहे निरीक्षण और सहायता की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और अनुपालन न करने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शहरी क्षेत्रों के आसपास के प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का भी निर्देश दिया गया।

श्री यादव ने दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से अनुरोध किया कि वे शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को और बेहतर बनाएं और आगामी दिनों में दिल्ली-एनसीआर की समग्र प्रगति की समीक्षा के लिए उन्हें संकलित करें। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को धन का तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के मापदंडों को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री भूपेंद्र यादव ने कार्य योजनाओं और हरित गतिविधियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल दिया ताकि प्रदूषण नियंत्रण एक सच्चा जनभागीदारी आंदोलन बन सके।

विशिष्ट सुझाव देते हुए, श्री भूपेंद्र यादव ने नगर निगम अधिकारियों को हरियाली बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत गर्मी प्रतिरोधी और कम पानी की आवश्यकता वाली स्वदेशी किस्मों की झाड़ियों और घासों के रोपण हेतु संबंधित वन विभागों के साथ साझेदारी करने की सलाह दी। उन्होंने विभिन्न सरकारी और नगर निगम एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का भी आह्वान किया ताकि अलग-थलग दृष्टिकोण और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके। शहरी स्वच्छता और बेहतर शहरी नियोजन के लिए शहरी खुले स्थानों के उपयोग हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का अनुरोध किया गया।

श्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में लोकप्रिय मार्गों और प्रमुख यातायात गलियारों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद कम से कम इन प्रमुख मार्गों पर संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कार्य योजनाएं न केवल वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार होनी चाहिए, जिसमें बढ़ते हुए ठोस अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थलों की अग्रिम पहचान शामिल हो।

बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीएसपीसीबी) के प्रतिनिधि, जिला अधिकारी और नगर आयुक्त (गाजियाबाद) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नोएडा प्राधिकरण) उपस्थित थे।

भारतीय नौसेना उप प्रमुख की मालदीव यात्रा - अभ्यास एकता - 2025 का समापन

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, 15 से 17 दिसंबर 2025 तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'एकता 2025' के समापन समारोह में भाग लेना है।

अभ्यास एकता, जिसकी शुरूआत 2017 में हुई थी, भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास के 8वें संस्करण में इंटरऑपरेबिलिटी और परिचालन तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक प्रोफेशनल बातचीत देखी गई। गतिविधियों में तकनीकी और कॉम्बैट डाइविंग, बोर्डिंग ऑपरेशंस, फायरिंग अभ्यास, विध्वंस और विस्फोटक प्रबंधन, असममित युद्ध रणनीति और विशेष हेली-बोर्न ऑपरेशन अभ्यास शामिल थे।

माले पहुँचने पर, भारतीय नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी से मुलाकात की। इस दौरान हुई चर्चाओं में मुख्य रूप से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करने, प्रशिक्षण भागीदारी को बढ़ाने, नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने और चल रही रक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सूचना साझाकरण को और उन्नत बनाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर 2025 को माले में आईएनएस शारदा पर आयोजित एक समारोह में, डीसीएनएस ने मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी को एमएनडीएफ कोस्ट गार्ड शिप हुरावी के लिए ऑपरेशनल स्पेयर पार्ट्स की एक खेप भी सौंपी।

भारतीय नौसेना उप प्रमुख की मालदीव की यह पहली यात्रा, क्षेत्रीय साझेदारों के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह दौरा भारत के 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और क्षेत्र में 'सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति' (महासागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग को रेखांकित करता है।

खाकी पर गंभीर आरोप: युवक ने थाना प्रभारी व दो सिपाहियों पर रुपए छिनने का लगाया आरोप

पीड़ित के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज, उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार

खखरेरू / फतेहपुर जनपद फतेहपुर हाल ही में आईजीआरएस निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, लेकिन इसी बीच खखरेरू थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है।

थाना क्षेत्र के जहांगीर नगर गहुरा निवासी आसिफ पुत्र सफीक अहमद ने खखरेरू थाना प्रभारी सहित दो सिपाहियों पर ₹28,000 नकद एवं ईंट भट्टे के हिसाब की डायरी जबरन छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत आईजी जोन प्रयागराज एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को लिखित तहरीर देकर की है।

आसिफ के अनुसार, 4 दिसंबर को वह अपने ईंट भट्टे पर ईंटों की बिक्री कर रहा था, तभी खखरेरू थाने से दो सिपाही—जिनके नाम अजीत सिंह एवं दीपक बताए गए हैं—भट्टे पर पहुंचे और थाना प्रभारी द्वारा बुलाने की बात कहकर उसे थाने चलने को कहा।

युवक ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से थाने के लिए रवाना हुआ, इसी दौरान एक सिपाही उसकी बाइक पर पीछे बैठ गया। जब वे डुडिया पुर गांव के समीप पहुंचे तो पीछे बैठे सिपाही ने उसकी जेब से ₹28,000 नकद एवं बिक्री का हिसाब लिखी डायरी निकाल ली। विरोध करने पर उसे धमकाते हुए थाने ले जाया गया।

एससी/एसटी एक्ट में मुकदमे का विवाद

सूचना मिलने पर युवक के दोनों भाई थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से जानकारी मांगी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के विरुद्ध गांव के मुकेश पुत्र शिवलाल द्वारा एससी/एसटी एक्ट की तहरीर दी गई है।

पीड़ित के अनुसार, जब कथित शिकायतकर्ता के पिता शिवलाल को थाने बुलाया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की तहरीर देने से इनकार किया और सीसीटीवी जांच की मांग की। इसके बाद पुलिस ने दबाव बनाकर युवक से झूठा प्रार्थना पत्र लेकर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया तथा युवक का 151 में चालान कर एसडीएम न्यायालय भेज दिया।

उच्चाधिकारियों से गुहार

पीड़ित युवक ने आईजी जोन प्रयागराज के समक्ष पेश होकर

झूठे एससी/एसटी मुकदमे की जांच,

छिने गए ₹28,000 व हिसाब की डायरी की बरामदगी,

एवं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

इस मामले में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि युवक के आरोप मनगढ़ंत है एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत होने के कारण युवक अनर्गल आरोप लगा रहा है ।

अन्ना मवेशियों की समस्या को लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

खखरेरू / फतेहपुर नगर पंचायत खखरेरू क्षेत्र में अन्ना मवेशियों की बढ़ती समस्या से परेशान सैकड़ों किसानों ने सोमवार को लोहरपुर चौराहे पर बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके पश्चात किसान एकजुट होकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी (ईओ) की अनुपस्थिति के चलते किसानों को निराशा का सामना करना पड़ा।

किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा कई बार अधिशासी अधिकारी हरेंद्र सिंह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। नायब तहसीलदार द्वारा भी ईओ से बात करने की कोशिश की गई, परंतु सफलता नहीं मिली। इससे आक्रोशित किसानों ने अंततः नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की।

किसानों ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के लोहरपुर, प्रतापपुर, सलवन, सोथरापुर सहित आसपास के गांवों में अन्ना मवेशियों का आतंक पूरी तरह फैला हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद अपनी फसलों को बचाने में असहाय नजर आ रहे हैं। आवारा गोवंशों द्वारा मटर, चना, लाही एवं गेहूं जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में किसानों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अन्ना मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

इस मौके पर अखिलेश सिंह, मनोज सिंह, दिलीप सिंह, सत्येंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, उदयभान सिंह, रोहित कुमार, ज्ञान सिंह, राम अभिलाष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे

तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक की मौत, तीन गंभीर घायल

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के दरिया मऊ पुलिया के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार दो बाइकों के बीच आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भदौहा गांव निवासी रमेश कुमार पुत्र जब्बार (उम्र लगभग 40 वर्ष) अपनी पत्नी फूलन देवी एवं पुत्र अंशु के साथ रविवार को अपने साढ़ू के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सोमवार शाम करीब 5 बजे वह गुरसंडी से अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान धाता की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक से दरिया मऊ पुलिया के पास आमने-सामने टक्कर हो गई।

दुर्घटना में रमेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी फूलन देवी एवं पुत्र अंशु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मौके पर एक बाइक सवार की मौत हो गई है गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को मंझनपुर इलाज के लिए भेज दिया दिया गया है

देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म 'स्पर्श' पर 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगी पंजीकृत हुए

पुराने विवादों के 94.3 प्रतिशत मामले सुलझा लिए गए; शिकायतों के निवारण का औसत समय 56 दिनों से घटकर 17 दिन हो गया

(जीएनएस)।

सही समय पर सही पेंशनभोगी को सही पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा (स्पर्श), जो डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है, देश का पहला संपूर्ण डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। प्रयागराज स्थित पीसीडीए (पेंशन) के माध्यम से रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा संचालित 'स्पर्श' ने नवंबर, 2025 तक भारत और नेपाल में 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगियों को अपने साथ जोड़ा है। यह 45 हजार से अधिक एजेंसियों द्वारा पहले प्रबंधित खंडित प्रणाली को एक एकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल ढांचे से प्रतिस्थापित करता है।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: पुराने सिस्टम से संबंधित 94.3 प्रतिशत विसंगतिपूर्ण मामलों का समाधान हो गया है : पिछली प्रणाली से स्थानांतरित किए गए 6.43 लाख विसंगतिपूर्ण मामलों में से 6.07 लाख मामलों को पेंशनभोगियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना सामान्य कर दिया गया है।

बुजुर्गों और तकनीकी रूप से कम जानकार पेंशनभोगियों के लिए व्यापक पहुंच : देश में 284 'स्पर्श' पहुंच कार्यक्रम और 194 रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान 8 हजार से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बढ़ी हुई पारदर्शिता और शिकायत निवारण : पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और आसानी से सुधार संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निवारण का औसत समय अप्रैल, 2025 में 56 दिन से घटकर नवंबर, 2025 में 17 दिन हो गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रक्षा लेखा विभाग ने 73 प्रतिशत संतुष्टि अंक प्राप्त किया है जिससे यह मंत्रालयों/विभागों में 5 वें स्थान पर है।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र 4.0 अभियान : रक्षा एवं पेंशनभोगी विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) 4.0 अभियान (1-30 नवंबर, 2025) के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग ने 202 कार्यालयों, 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और 15 भागीदार बैंकों को सक्रिय किया है जिन्हें 27 नोडल अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। 30 नवंबर, 2025 तक रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 20.94 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है।

वितरण : वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा पेंशन बजट के अंतर्गत 1,57,681 करोड़ रुपये का वितरण 'स्पर्श' के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर किया गया। जुलाई, 2024 में लागू वन रैंक वन पेंशन-III के अंतर्गत मात्र 15 दिनों में 20.17 लाख लाभार्थियों को 1,224.76 करोड़ रुपये का त्वरित वितरण संभव हुआ।

'स्पर्श' देश की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है और रक्षा कर्मियों के लिए एकमात्र पूर्णतः एकीकृत डिजिटल पेंशन समाधान है। यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मान, देखभाल और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय रेल ने उर्वरक लोडिंग में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे देश भर के किसानों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है

चालू वित्त वर्ष में अब तक भारतीय रेल ने 17,168 उर्वरक रैक लोड किए हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली है

(जीएनएस)।

भारतीय रेल भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे देश में उर्वरकों की सुचारू और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करता है। इस वर्ष 30 नवंबर तक उर्वरक की लोडिंग 17,168 रेक तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 15,369 रेक की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि रेलवे नेटवर्क के कुशल संचालन को दशार्ती है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को बुवाई के लिए समय पर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने उर्वरक और खाद्यान्न ले जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी है। इससे देश भर के राज्यों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

आवश्यक माल ढुलाई सेवाओं को मजबूत करके रेलवे लाखों किसानों की मदद कर रहा है। यह ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। यह प्रदर्शन भारतीय रेल की राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प और भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

भारतीय रेल विश्वसनीय, व्यापक और कुशल परिवहन प्रदान करके पूरे देश में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरक रैकों की प्राथमिकता के आधार पर आवाजाही करके, रेलवे किसानों को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे बिना किसी देरी के कृषि कार्य कर सकें।

रक्षा मंत्री रक्षा संपदा दिवस समारोह में शामिल होंगे; विभाग ने अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली छावनी स्थित रक्षा संपदा भवन में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर वे देश भर में फैले 61 छावनी बोर्डों के रक्षा भूमि प्रबंधन और नगर प्रशासन के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे।

इस वर्ष के समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि विभाग अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो उस विरासत का स्मरणोत्सव है जिसकी शुरूआत 1765 में हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पहली छावनी स्थापित की गई थी। इसके बाद डेढ़ शताब्दी में दानापुर (1766), मेरठ (1803), अंबाला (1843), दिल्ली (1915) आदि जैसी छावनियों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत में रक्षा और भूमि प्रशासन की नींव रखी। बाद में 16 दिसंबर, 1926 को रक्षा मंत्रालय के अधीन भूमि और छावनी विभाग के रूप में इस विभाग को औपचारिक रूप दिया गया।

रक्षा संपदा विभाग आज रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की सबसे बड़ी भू-संपत्ति का प्रबंधन करता है। इतिहास में अपनी गहरी जड़े जमाए हुए विभाग ने आधुनिकीकरण की एक असाधारण यात्रा तय की है, जिसने स्वयं को डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी-आधारित भूमि प्रबंधन में अग्रणी बना लिया है। विभाग ने छावनी के 20 लाख निवासियों को शत-प्रतिशत नगरपालिका सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराकर ई-छावनी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए विभाग के प्रयासों को सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिली है और इसे 'जल संचय जन भागीदारी' के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विभाग ने पुराने भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण कर दिया है, जिससे भविष्य में उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। संपूर्ण फाइल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है और देशव्यापी स्तर पर एक सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-समर्थित फाइल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया गया है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

सबसे अधिक आवश्यक मतदाता हैं, चुनाव प्रक्रिया में उनका विश्वास सदैव रहे बना

चुनाव सुधार पर सड़क से संसद तक चर्चा तेज हुई। शायद यह जरूरी भी था, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी देश के 12 राज्यों व वेंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण तेज गति से हो रहा है पर यह भी देखने वाली बात है कि इस पर सियासत भी उसी स्पीड से चल रही है। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी प्रकरण के जवाब में जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया और अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने झूठ पैलाया है और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ताकि जिनकी मृत्यु हो गईं उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हैं उनके नाम जुड़ जाएं, जो दो जगह मतदाता हैं उनके नाम कट जाएं और जो विदेशी नागरिक हैं उनको चुन-चुनकर हटाया जाए। उन्होंने कहा क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, यह घुसपैठिए तय करेंगे। एसआईआर से वुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। निर्णय करना पड़ेगा कि देश की संसद और विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं? इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए और अमित शाह से पूछा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में चुनाव आयुक्तों को पूरी तरह माफी दी जाएगी, इसका जवाब दें। हरियाणा का एक उदाहरण इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को दिया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इस दौरान उन्होंने आरएसएस का नाम लिया। राहुल ने कहा कि समानता की भावना से आरएसएस को दिक्कत है। संघ ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें देखा और कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा कीजिए। नेता प्रतिपक्ष का मतलब ये नहीं कि वुछ भी बोलें। राहुल ने बहस की शुरूआत खादी से की। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक पैब्रिक की तरह ही है। कपड़ा कई धागों से बनता है। वैसे ही हमारा देश भी कई लोगों से मिलकर बनता है। देश के सारे धागे एक जैसे और अहम हैं। देश के सभी लोग बराबर हैं। राहुल ने कहा कि वोट के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता दल ने कब्जा कर लिया है।

ईसी, सीबीआई, ईडी सब पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिला हुआ है। हमने इस बात के सुबूत दिए। सरकार इसी का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त चुनने की प्रव्रिया को क्यों बदला गया। इस प्रव्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पर चलती है। सत्ता पक्ष ही चुनाव आयोग को चला रहा है। राहुल ने ब्राजील की मॉडल का भी जिव्र किया। उन्होंने कहा कि ब्राजील की मॉडल का नाम 22 बार वोटर लिस्ट में आया। एक महिला का नाम 200 बार वोट लिस्ट में आया। चुनाव आयोग को सीसीटीवी पुटेज को वंट्रोल करने का मतलब क्या है और क्यों इस पुटेज को वुछ समय बाद हटाने का पैसला किया गया? पुटेज नष्ट करने की ताकत क्यों दी गई? चुनाव आयुक्तों पर सजा का प्रवधान क्यों हटाया गया? हरियाणा चुनाव का जिव्र करते हुए राहुल ने कहा कि हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है तो उसे उठ रहे प्रश्नों का उत्तर प्रथमिकता से देना चाहिए।

पारदर्शिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। चुनाव आज से दो दशक पहले वैसे होते थे, इससे ज्यादा जरूरी है कि अब जो चुनाव हों प्रश्नों से पटे हों। लोकतंत्र के असली मालिक व रक्षक मतदाता हैं, जनता है और उसका चुनाव प्रव्रिया पर पूरा विश्वास होना चाहिए।

नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा

समग्र स्वास्थ्य और कल्याणकारी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेता नई दिल्ली में एकत्रित होंगे

(जीएनएस)।

17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक संवाद का आयोजन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सह-आयोजित यह शिखर सम्मेलन संतुलित, समावेशी और सतत स्वास्थ्य प्रणालियों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाएगा।

इस शिखर सम्मेलन का विषय है ह्रसंतुलन की बहाली : स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यासह्व। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों में असमानताओं, पर्यावरणीय तनाव और बढ़ती दीर्घकालिक बीमारियों के समय में यह शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करने के साथ-साथ विज्ञान, साक्ष्य और उत्तरदायित्वपूर्ण अभ्यास के आधार पर इसकी भूमिका को सुदृढ़ करेगा। 2023 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन से मिली सफलता आगे बढ़ाते हुए, नई दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में पारंपरिक चिकित्सा को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 के मार्गदर्शन में आयोजित यह शिखर सम्मेलन इस बात पर केंद्रित होगा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण में किस प्रकार सार्थक योगदान दे सकती हैं। इस दौरान उभरते साक्ष्यों, नवाचारों और नीतिगत मार्गों पर प्रकाश डाला जाएगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित, प्रभावी और नैतिक एकीकरण का समर्थन करते हैं।

शिखर सम्मेलन की तकनीकी चचाओं का शुभारंभ संतुलन बहाल करने पर एक उच्च स्तरीय पूर्ण सत्र से होगा, जिसमें ज्ञान, पहुंच, शासन और वैश्विक स्वास्थ्य में असंतुलन के कारणों की जांच पड़ताल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि संतुलन बहाल करने का आज के समाजों के लिए क्या अर्थ हो सकता है। वैश्विक नेता और विशेषज्ञ इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि वैज्ञानिक सटीकता, न्यायसंगत शासन, जैव विविधता संरक्षण, स्वदेशी अधिकार और विविध ज्ञान प्रणालियाँ मिलकर किस प्रकार एक अधिक न्यायसंगत और लचीले वैश्विक स्वास्थ्य भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। सत्र में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु समन्वित वैश्विक कार्रवाई के लिए उभरते विचारों को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विज्ञान और नवाचार पर विशेष बल दिया जाएगा। एक पूर्ण सत्र में पारंपरिक चिकित्सा में प्रगति लाने के लिए विज्ञान में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें गहन शोध, निरंतर वित्त पोषण, कार्य प्रणाली में सामंजस्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। चचाओं में इस बात पर बल दिया जाएगा कि सतत विकास और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में साक्ष्य-आधारित योगदानकर्ता के रूप में पारंपरिक चिकित्सा को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक निवेश और वैज्ञानिक सहयोग कितने आवश्यक हैं।

एक अन्य पूर्ण सत्र में संतुलन, सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना पर

ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 की दृष्टि और प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के अनुभवों, विशेष रूप से दक्षिण- पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर, यह सत्र प्रदर्शित करेगा कि नीतिगत, विधायी और नियामक प्रगति के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कैसे एकीकृत किया जा रहा है। सुदृढ़ शासन ढांचे, गुणवत्ता आश्वासन और अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग का महत्व प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा।

यह शिखर सम्मेलन जवाबदेही, मानकों और आंकड़ों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और यह पता लगाएगा कि पारंपरिक चिकित्सा में प्रगति को कैसे मापा और जिम्मेदारी से निर्देशित किया जा सकता है। एक समर्पित पूर्ण सत्र मानकीकृत आंकड़ों, पारदर्शी रिपोर्टिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार, मानव- केंद्रित उपयोग की भूमिका की जांच करेगा। चचाओं में प्राचीन ज्ञान, सांस्कृतिक अखंडता और सामुदायिक विश्वास के प्रति सम्मान पर जोर दिया जाएगा, साथ ही ऐसे जवाबदेह ढांचे की मांग की जाएगी जो ज्ञान के अनेक तरीकों को मान्यता दें और संसाधनों के निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करें।

तीन दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भविष्योन्मुखी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के भीतर पारंपरिक चिकित्सा का विनियमन और एकीकरण; स्वदेशी लोगों के साथ ज्ञान का सम्मानजनक आदान-प्रदान; जैव विविधता का संरक्षण और औषधीय संसाधनों का सतत उपयोग; बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और अनुसंधान, शिक्षा तथा व्यवहार में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार अनुप्रयोग शामिल है।

इस कार्यक्रम में 25 से अधिक सत्रों में 170 से अधिक विशेषज्ञ वक्ता शामिल होंगे जो विज्ञान, नीति, व्यवहार और सामुदायिक नेतृत्व के दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करेंगे। 21 चयनित नवाचारों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से उभर रहे नए दृष्टिकोणों, उत्पादों और समाधानों पर प्रकाश डालेंगे। शिखर सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और जैव-सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुभवों को भी उजागर किया जाएगा, जो स्वास्थ्य, संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करेगा।

इसमें सरकारी नेता, वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के हितधारक और नागरिक समाज संगठन शामिल होंगे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व के साथ, यह शिखर सम्मेलन संवाद और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। अपने समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिससे नई दिल्ली में स्थल पर और ऑनलाइन, दोनों तरह से दुनिया भर के लोग इसमें भाग ले सकेंगे।

इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य आधार, नीतिगत वातावरण और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से नई पहलों, सहयोगों, प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं की घोषणा होगी। इन परिणामों से स्वास्थ्य के प्रति अधिक समग्र, लचीले और टिकाऊ दृष्टिकोण विकसित होने की उम्मीद है, जो व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य और विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे।

वर्ष 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन ने इस क्षेत्र में वैश्विक ध्यान, डेटा और प्रौद्योगिकियों को लाकर एक मजबूत नींव रखी। 2025 का शिखर सम्मेलन इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक नवाचार, शासन और जवाबदेही का गहन अध्ययन करेगा साथ ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और उन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर भी बल देगा जिन पर वे निर्भर हैं।

विश्व ऐसे स्वास्थ्य समाधानों की तलाश कर रहा है जो न केवल प्रभावी हों बल्कि न्यायसंगत और टिकाऊ भी हों, ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। विभिन्न आवाजों और ज्ञान प्रणालियों को एक साथ लाकर, यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में व्यक्तियों, समुदायों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करने की दिशा में एक सामूहिक मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखता है जब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण के भविष्य की पुनर्कल्पना की जा रही है।

'घरवाली पेड़वाली' ने मुंबई में निकाली भव्य और अनोखी बारात

यूपी। नए हल्के-फुल्के फैमिली कॉमेडी शो 'घरवाली पेडवाली' के लॉन्च से पहले प्रमोशन के लिए पहली बार मुंबई की सड़कों पर एक भव्य और अनोखी बारात निकाली, जिसने मुंबई को रंग, संगीत और मस्ती से भर दिया। शो के मुख्य किरदार जीतू पांडे (पारस अरोड़ा) अपनी दो दुल्हनों - सावी (सीरत कपूर) और लतिका (प्रियंवदा कांत) के साथ एक सजी-धजी रंगीन बस में सवार होकर शहर के कई मशहूर इलाकों से गुजरे। यह अनोखी बारात अंधेरी, जुहू, बांद्रा और वर्ली से होती हुई अमिताभ बच्चन के 'जलसा', शाहरुख खान के 'मन्नत', सलमान खान के 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' और ईशा अंबानी के 'गुलिता' जैसे चर्चित ठिकानों के पास से गुजरी। रास्ते में बारात को देखने वाले लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यहां बता दें कि एण्डटीवी और जी5 पर 'घरवाली

पेड़वाली' सोमवार से शुक्रवार, रात दस बजे प्रसारित है।

इस बारात में शो की पूरी ऑन-स्क्रीन फैमिली, रिश्तेदार और ऑफिस के किरदार नजर आए। इनमें शामिल थे- जीतू के माता-पिता गीता पांडे (गीता बिष्ट) और रीता पांडे (ऋचा सोनी), रमेश पांडे (हर्ष वशिष्ठ), सुरेश पांडे (बृज भूषण शुक्ला), दादाजी (बबलू मुखर्जी), रितिका बुआ (प्रीति सहाय दुबे), पनौती मामा (अमिताभ घाणेकर), सावित्री (प्रियंवदा सिंह), टिल्लूमल (सुदीप सारंगी), लट्टू (विनायक सिंह) और पप्पी (लोटा तिवारी)। इससे यह प्रमोशनल इवेंट बिल्कुल शो की तरह ही एक बड़े पारिवारिक जश्न में बदल गया।

बारात का सबसे खास पल बांद्रा बैंडस्टैंड पर देखने को मिला, जहां अचानक एक सरप्राइज फ्लैश मॉब शुरू हुआ। डांसर्स की जोशीली परफॉर्मेंस ने आम शाम को एक रंगीन उत्सव में बदल दिया। सड़क पर चलते लोग रुक गए, मोबाइल कैमरे चल पड़े और हर तरफ तालियों व मुस्कान की गूंज सुनाई दी। एक दूल्हा और दो दुल्हनों- जिसमें एक असली और दूसरी रहस्यमयी है- के दिलचस्प नजारे के साथ यह दृश्य शो की कहानी को बखूबी दर्शा रहा था। शो को टीवी स्क्रीन से बाहर निकालकर मुंबई की सड़कों तक ले जाना दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, जिसने हर उम्र के लोगों का ध्यान खींचा।

नमामि कृष्णम ने नृत्य के जरिए कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व बताया

लखनऊ भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी सांस्कृतिक संस्था घृताक्षी संगीतशाला के तत्वावधान में आज शाम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में आयोजित नमामि कृष्णम ने नृत्य के जरिए कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व बताया। संगीत से सजे कार्यक्रम में मुस्कान खत्री के नृत्य निर्देशन में दिव्या, अरु, वंदिता सहित अन्य कलाकारों ने गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर अपने गुरू के चरणों में अगाध श्रद्धा अर्पित की। गुरू नमन के उपरान्त रेयांशा, पूर्वी, मेधा, रश्मि, श्रद्धा, छवी,नीरज और आकृति ने नीर भरन कैसे जाऊं और मधुवन में राधिका नाची रे पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

कार्यक्रम के अगले सोपान में मुस्कान खत्री ने हे परमेश्वर पर अपनी

नृत्य प्रस्तुति से ईश्वर की महिमा का बखान किया। इसी प्रकार मृदुल और अक्षय लांबा ने कृष्ण-सुदामा चरित्र का भावाभिनय प्रस्तुत किया।मन को मोह लेने वाली इस पेशकश के उपरान्त घृताक्षी संगीतशाला के कलाकारों ने महाभारत लघु नृत्य नाटिका के जरिए भगवान श्री कृष्ण के बताये कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व समझाया। हृदय को रोमांचित कर देने वाली इस प्रस्तुति के बाद चित्रांश अस्थाना, मनप्रीत, अर्थव, सूर्यांश, संदीप ने अपनी सुमधुर आवाज में राग यमन में निबद्ध सरस्वती वंदना की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी।

इस मौके पर प्रो. मीरा दीक्षित, प्रमोद मिश्रा, जय किशन श्रीवास्तव, रोजी, शिवांगी और आलोक शर्मा को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर गुरू सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सतेन्द्र आर्या, मुस्कान खत्री, पंडित आदित्य द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों और प्रदर्शनियों की स्थापना और आधुनिकीकरण

वर्तमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में देश भर में बावन (52) पुरातात्विक स्थल संग्रहालय हैं। राज्यवार सूची अनुलग्नक झ 1 में संलग्न है।

एएसआई द्वारा विकसित नए संग्रहालयों, दीघाओं और अनुभवात्मक स्थलों की सूची अनुलग्नक झ क्क में संलग्न है।

केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे देश में मौजूदा पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों का वार्षिक रखरखाव और समय-समय पर उन्नयन करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान योजना संचालित करता है जिसके तहत नए संग्रहालयों की स्थापना/मौजूदा संग्रहालयों के विकास/संग्रहालयों के डिजिटलीकरण और केंद्र/राज्य सरकारों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियों, विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, आईकॉम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक संस्थानों के साथ जनभागीदारी को बढ़ाया है। इनसे दृश्यता बढ़ती है, जनसंपर्क गतिविधियों को समर्थन मिलता है और राष्ट्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए व्यापक जनहित उत्पन्न होता है।

पुरातत्व संग्रहालय स्थलों की व्याख्या और प्राचीन वस्तुओं के सुरक्षित प्रदर्शन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे सांस्कृतिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। वे क्षेत्रीय शिल्पों और व्यंजनों को बढ़ावा देने सहित स्थानीय रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करते हैं, और परिणामस्वरूप संबंधित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में योगदान देते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले उत्सव

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा देश भर में 362 सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए गए हैं। यह सभी केंद्र एक स्वायत्य संस्थान हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा अपने सदस्य राज्यों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों/उत्सवों में भाग लेने के लिए अन्य जोन/राज्यों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ने महाकुंभ-2025, काशी तमिल संगमम, राष्ट्रीय एकता दिवस और वंदे भारतम कार्यक्रम आदि में भाग लिया। इन उत्सवों के माध्यम से दर्शकों और कला प्रेमियों को देश के अन्य क्षेत्रों की कलाओं और गीत, संगीत और नृत्यों का आनंद लेने और समझने का अवसर मिलता है। ये उत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जानने और समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

साल 2024-25 के दौरान, देश में अलग-अलग सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करने के लिए सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को 11121.65 लाख रुपये आवंटित/जारी किए गए हैं।

सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा अपने सदस्य राज्यों में आयोजित अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों/त्योहारों में 55,519 कलाकारों/प्रस्तुतकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2323 कलाकार/प्रस्तुतकर्ता ओडिशा के थे।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

पूर्व सैनिकों का कल्याण और पुनर्वास

(जीएनएस)।

वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, पूर्व सैनिकों की संख्या 28,31,109 है। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) ने पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाएं चलाई हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय की योजनाओं का विवरण

डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना: डीजीआर, विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।

डीजीआर तकनीकी सेवा योजना: डीजीआर सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों/परिसरों में'तकनीकी सेवाओं' के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं प्रदान करता है।

पूर्व सैनिक कोयला लदान एवं परिवहन योजना (केवल अधिकारियों के लिए): यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर संचालित की जाती है। सीआईएल के वर्ष 2013 के समझौता ज्ञापन से हटने के बाद वर्तमान में यह योजना विचाराधीन है।

पूर्व सैनिक के लिए कोयला टिपर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए): इस योजना को कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन योजना से जोड़ा गया है।

विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना: 65 वर्ष तक की आयु की विधवाएं और 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग सैनिक इस योजना के लिए नामांकन के पात्र हैं।

तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) वितरक पद के आवंटन हेतु 8 प्रतिशत आरक्षित कोटा के तहत डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना: युद्ध विधवाओं/युद्ध में शहीद हुए व्यक्तियों के आश्रितों, युद्ध के दौरान परिचालन क्षेत्र में सेवा के दौरान निशक्त हुए व्यक्तियों, सैन्य सेवा के कारण या उससे संबंधित कारणों से सेवारत रहते हुए शहीद हुए व्यक्तियों की विधवाओं/आश्रितों और सैन्य सेवा या उससे संबंधित कारणों से शांति काल में दिव्यांग हुए पूर्व सैनिकों सहित पूर्व सैनिक इस योजना के लिए पात्र हैं।

कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा संचालित (सीओसीओ) खुदरा दुकानों का प्रबंधन: इच्छुक पूर्व सैनिक अधिकारी और जेसीओ, जिन्होंने किसी अन्य सरकारी/डीजीआर योजना का लाभ नहीं उठाया है, को तेल कंपनी द्वारा आगे चयन के लिए अनुरोध के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है।

एनसीआर/पुणे में सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन: इस योजना में पंजीकृत इच्छुक पूर्व सैनिकों को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।

एनसीआर में मदर डेयरी के दूध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटन: पूर्व-शिक्षित वयस्कों (पूर्व सैनिकों) को 60 वर्ष की आयु तक दूध/सफल (फल एवं सब्जी) बूथों के लिए अलग से पंजीकृत किया जाता है। वे इन दुकानों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।

पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) में शामिल करना: सरकार की पीएमबीजेपी योजना का उद्देश्य देशभर में जेनेरिक दवाओं की दुकान स्थापित करना है ताकि सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। डीजीआर ने इस योजना की शुरूआत जून 2023 में की थी।

पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम: भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी डीजीआर के प्रशिक्षण निदेशालय की है ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों के कौशल को नागरिक क्षेत्र में सुचारू रूप से उपयुक्त रोजगार के लिए बढ़ाया जा सके।

अधिकारियों के लिए - पाठ्यक्रम शुल्क का 60 प्रतिशत रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा और 40 प्रतिशत प्रत्येक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएं भी उपरोक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

जेसीओ/ओआर और समकक्षों के लिए - पाठ्यक्रम शुल्क का शत-प्रतिशत भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं डीजीआर द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

महानिदेशालय पुनर्वास रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं से कुल 67,316 पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पुनर्वास महानिदेशालय के कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों और योजनाओं के अंतर्गत कुल 11,589 सेवानिवृत्त और पूर्व-सेवानिवृत्त अधिकारियों/जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों को पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को भी उपरोक्त विवरण के अनुसार रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जा रहा है।

घने कोहरे में सावधानी से चलाए वाहनः डीसी

-शीतलहर व ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतें नागरिकः डीसी

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने आमजन सहित पशुओं को सर्दी व शीतलहर से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि आमजन सावधानी बरतकर सर्दी से अपना व अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। सर्दी से बचाव के लिए आमजन अपने पास पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। घर में ठंडी हवा का प्रवेश रोकने के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। गर्म कपड़े पहनें ताकि ठंड बिल्कुल न लगे। खुद को सूखा रखें और पानी में भीगने से बचें। शरीर की

गरमाहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढककर रखें। गीले कपड़े तुरंत बदलें। हाथों में दस्ताने रखें। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें।

` डीसी ने बताया कि सिर पर टोपी या मफलर पहने, स्वास्थ्य वर्धक भोजन लें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पीएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। शराब का सेवन न करें, यह शरीर के तापमान को कम करता है। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जरूरत के अनुसार ही रूम हीटर का प्रयोग करें तथा रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें।

उन्होंने कहा कि शीत-घात से बचने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो/टीवी/समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है। डीसी ने बताया कि शीतलहर के दौरान पशुओं और पशुधन को जीवन यापन के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। रात के समय पशुओं के आवास को सभी तरफ से ढक दें ताकि ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचा जा सके। शीत लहर के दौरान जानवरों को खुले क्षेत्र में न छोड़ें। जानवरों को ठंडा चारा और ठंडा पानी देने से बचें। पशु आश्रय में नमी और धुएं को नहीं रहने दें। वहीं आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर सहायता लें।

कोहरे में ओवरटेक करने से बचें

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि सर्दी के मौसम में घने कोहरे के दौरान विशेषकर सुबह और रात के समय कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में वाहन चालकों को सीमित गति में, अपनी निर्धारित लेन में रहकर और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए वाहन चलाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और नागरिक सुरक्षित यात्रा कर सकें। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धुंध के मौसम में गलत दिशा में वाहन न चलाएं और धुंध के समय जहां तक संभव हो ओवरटेक करने से बचें।

रेडक्रॉस सचिव बिजेंद्र सिंह सौरोत ने संभाला कार्यभार

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। राज्यपाल हरियाणा एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अध्यक्ष के आदेशों की अनुपालना में बिजेंद्र सिंह सौरोत ने सोमवार को 15 दिसंबर को जिला रेडक्रॉस सोसायटी, रेवाड़ी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।`

वर्तमान में बिजेंद्र सिंह सौरोत जिला रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद के सचिव है। पदभार संभालने के साथ ही सचिव ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी रेवाड़ी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा से मुलाकात की तथा कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। डीसी अभिषेक मीणा ने सचिव को दिव्यांगजन एवं सामाजिक अंत्योदय के लिए आवश्यक कदम उठाने बारे दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सचिव

द्वारा रेडक्रॉस के कर्मचारियों के साथ बैठक ली गई तथा स्टाफ से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली गई।

` सचिव ने रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों जैसे टी बी प्रोजेक्ट, टी आई प्रोजेक्ट, रक्तदान सेवाएं, नशा मुक्ति अभियान, प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। सचिव ने कहा कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी रेवाड़ी समाज के सभी वर्गों खासकर दिव्यांगजन, बेसहारा बुजुर्गों के कल्याण कार्य करने में सदैव तत्पर रहेगा।

एसडीएम बावल ने बावल क्षेत्र के एसएससी जोनल मैनेजर के साथ की बैठक

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। एसडीएम बावल मनोज कुमार द्वारा उपमंडल बावल में आने वाले सभी सी.एस.सी सेंटर पर योजनाओं व सेवाओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया। जिसमें जिलाधिकारी सी.एस.सी रेवाड़ी व बावल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के जोनल मैनेजर उपस्थित रहे। सी.एस.सी जिलाधिकारी रेवाड़ी ने बताया कि आयुष्मान भारत के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन व कार्ड की डिलीवरी, नया आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट, लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन व परिवार पहचान पत्र का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी साइट पर जाकर खुद यह कार्य करता है, तो कोई शुल्क नहीं लगता और सभी सी.एस.सी सेंटर पर फीस की लिस्ट लगाने बारे हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि आम नागरिक सी.एस.सी सेंटर पर फीस की लिस्ट को देखकर ही अपने शुल्क की अदायगी करें। कोई सी.एस.सी सेंटर संचालक अधिक राशि वसूल करता है और सी.एस.सी सेंटर पर लिस्ट नहीं लगी हुई है, तो इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी (ना0), बावल के कार्यालय मे कमरा नं0 114 में दें।

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का तय समय में करें निपटान : डीसी

जिला व उपमंडल स्तर पर सोमवार व वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लगाए जा रहे समाधान शिविर

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाडी। हरियाणा सरकार के निदेर्शानुसार जिला व उपमंडल स्तर पर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को लघु सचिवालय रेवाड़ी के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में डीसी अभिषेक मीणा ने आमजन की शिकायतें सुनी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का तय समय में निपटान करवाना सुनिश्चित करें।

` डीसी ने कहा कि आमजन को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए समाधान शिविरों का लाभ उठाना चाहिए। समाधान शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद

रहकर शिकायतों का निवारण करते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निवारण किया जा सके। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे मिलकर अपनी समस्या का निवारण करवा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आमजन की शिकायतों के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर राहत पहुंचाने का काम करें।

` सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में गोठड़ा टप्पा डहीना में रास्ते पर अवैध निर्माण व गांव निखरी में जोहड़ पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को जांच कर अवैध निर्माण हटवाने के निर्देश दिए। गांव निखरी में 60 साल से पुराने पेड़ कटवाये जाने की शिकायत पर डीसी ने डीएफओ को शिकायत की जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। गांव जड़थल की निवासी की बिजली बिल से संबंधित शिकायत पर डीसी ने डीएचबीवीएन के अधिकारियों को बिजली बिल की जांच करने के निर्देश दिए। इनके अलावा परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें आईं, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया। वहीं लंबित शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

` इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम जितेन्द्र कुमार, डीएसपी पवन कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

रेवाड़ी में 'नशा मुक्त रेवाड़ी' अभियान को मिली नई धार

पुलिस की जागरूकता पहल का विद्यार्थियों व आमजन ने किया स्वागत

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। जिले में नशे और साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ह्लनशा मुक्त रेवाड़ीह्व अभियान के तहत एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों, इसके सामाजिक व पारिवारिक नुकसान तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे से

संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी टअठअर हेल्पलाइन नंबर 1933 पर दी जा सकती है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के आगे आकर सहयोग कर सकें।

पुलिस प्रशासन की इस सराहनीय पहल का कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने स्वागत किया और एकजुट होकर ह्लनशा मुक्त रेवाड़ीह्व बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से ही नशे के खिलाफ इस लड़ाई को सफल बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों ने नशा एवं साइबर अपराधों से दूर रहने, समाज में जागरूकता फैलाने और कानून का सम्मान करने की शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देना और जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाना रहा।

महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु 'प्रोजेक्ट संवर्धन' विशेष अभियान का 17 दिसंबर को होगा शुभारंभ

300 सेशन - 03 बुधवार - हर बच्चे तक पहुंचे इस बार

(जीएनएस)। बलरामपुर

जनपद में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान ह्लप्रोजेक्ट संवर्धनह्व संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम एवं समुचित पोषण सुनिश्चित करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाना है।

अभियान के संबंध में डीएम विपिन कुमार जैन द्वारा प्रेस वार्ता की गई । उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत दिनांक 17 दिसंबर 2025 को जनपद के 300 पंचायत भवनों में वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का नियमित एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बच्चों के वजन, लंबाई एवं अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच कर उनके पोषण स्तर का आकलन किया जाएगा।

वीएचएसएनडी सत्रों में विशेष रूप से सैम एवं मैम श्रेणी के बच्चों की पहचान (चिन्हांकन) की जाएगी, ताकि उन्हें शासन की निर्धारित पोषण एवं उपचार योजनाओं से आच्छादित कर कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। चिन्हित बच्चों को आवश्यकतानुसार पोषण परामर्श, चिकित्सकीय देखरेख एवं रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग द्वारा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकताओं का संवेदीकरण (सेंसिटाइजेशन) किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी वीएचएसएनडी सत्रों में वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर सहित आवश्यक माप उपकरणों की उपलब्धता रहे।

इसके अतिरिक्त, जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर आदि आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने की अपील की गई है, ताकि किसी भी स्तर पर संसाधनों की कमी न रहे और अभियान सुचारु रूप से संचालित हो सके।

इस अभियान का क्रियान्वयन जिला स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाया जाएगा।

जिला प्रशासन द्वारा आमजन, विशेषकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी पंचायत भवन में आयोजित वीएचएसएनडी सत्र में उपस्थित होकर इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता द्वारा अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी सत्रों की निगरानी 300 नामित अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो केवल पर्यवेक्षक नहीं बल्कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगे। सत्र पंचायत भवनों पर आयोजित होंगे, जहां आवश्यक दवाएं, टीकाकरण, कोल्ड चेन एवं समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

श्लरठऊ सत्रों में आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अनिवार्य उपस्थिति के साथ स्पष्ट भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है, जबकि ग्राम प्रधानों की सक्रिय सहभागिता से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरियों की पहचान कर उनकी स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण परामर्श, रअट/टअट बच्चों की स्क्रीनिंग एवं आवश्यकतानुसार रेफरल किया जाएगा।

साथ ही पोषण एवं स्वच्छता पर व्यवहार परिवर्तन हेतु व्यावहारिक प्रदर्शन, परिवार नियोजन परामर्श तथा गर्भवती महिलाओं के लिए गोपनीय एएनसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सत्रों के उपरांत 48 घंटे के भीतर उच्च जोखिम वाले मामलों का अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की यह कार्ययोजना श्लरठऊ सत्रों को प्रभावी, समन्वित एवं जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

इस दौरान मीडिया बंधु , मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश रस्तोगी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त सीडीपीओ व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखो रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। साइबर थाना रेवाड़ी पुलिस ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखो रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान एमपी के जिला भोपाल के अराधना नगर कोटरा सुल्तानाबाद शारदा हॉस्पिटल हाल आबाद गंगा अपार्टमेन्ट गंगानगर एमपी निवासी कुलदीप कैथल के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

जांचकर्ता ने बताया की गत 3 जुलाई को सेक्टर-3 रेवाड़ी निवासी विजय कुमार गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। सोशल मीडिया पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का विज्ञापन देखने के बाद गत 15 मई को उसे एक व्हाट्सएप नंबर मिला था। जिसके बाद उसका

व्हाट्स पर एक महिला से संवाद होना शुरू हो गया। महिला ने अपना नाम मिस सरोज गुप्ता बताते हुए खुद को एसबीआई सिक्योरिटी लि. की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताया था। इन्वेस्टमेंट के लाभ के बारे में जानकारी देने के बाद महिला ने उसके पास एक लिंक भेजा था। उसे बल्क ट्रेडिंग और लॉगिन करने के बारे में बताया गया था। पहली बार पैसा इन्वेस्ट करने पर उसके खाते में अच्छा प्रॉफिट भी दशार्या गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी सरोज गुप्ता के बैंक खाते से 18 ट्रांजेक्शन के जरिए विभिन्न खाता नंबरों पर कुल 93 लाख 20 हजार 870/- रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उसने पैसा रिफंड कराने का प्रयास किया, तो उससे और पैसा जमा कराने के लिए कहा गया। इसके बाद उसे ठगी का पता चला। जिस पर पुलिस ने साइबर थाना रेवाड़ी में ठगी का मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त चार आरोपी महाराष्ट्र के अकोला के सिद्धार्थ नगर हाल आबाद पवन पार्क सोसाइटी न्यू तापडिया नगर महाराष्ट्र अकोला निवासी सतीश प्रकाश इंगले, उत्तराखंड के जिला नैनीताल के कांठगोदाम हाल आबाद उत्तराखंड के ट्रांजिट कैंप वार्ड नं 2 निवासी नीरज सिंह, बिहार के जिला गोपालगंज के गांव कोटवा खास हाल आबाद यूपी के जिला लखनऊ के राजीव नगर निवासी ओमप्रकाश प्रसाद व महाराष्ट्र के अकोला के ए विंग संकेत विहार अपार्टमेन्ट निवासी ओमप्रकाश अरुण मगर उर्फ ओम पाटिल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जो इस मामले में पुलिस ने रविवार को मामले में संलिप्त एक और आरोपी एमपी के जिला भोपाल के अराधना नगर कोटरा सुल्तानाबाद शारदा हॉस्पिटल हाल आबाद गंगा अपार्टमेन्ट गंगानगर एमपी निवासी कुलदीप कैथल को भी गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपी कुलदीप कैथले के खाते में ठगी के 50 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने आरोपी को पेश अदालत करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।

गन्ना क्रय केन्द्रो पर अलाहु नदारद ठण्ड से कराह रहा किसान

(जीएनएस)। कमलापुर,

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 65 किलोमीटर दूर जनपद सीतापुर की सहकारी गन्ना विकास समित कमलापुर क्षेत्र अन्तर्गत संचालित डालमिय भारत सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इकाई रामगढ चीनीमिल के गन्ना क्रय केन्द्र कमलापुर अ प्रथम, द्वितीय, त्रतीय पर किसानो को ठण्ड से बचाव के लिए अलाहु का कोई प्रबन्ध नही किया गया है ऐसा आलम जब देखने को मिल रहा है जब आए दिन जिलाधिकारी सीतापुर डाक्टर राजा गणपति आर, जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, व उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा आए दिन क्षेत्र मे संचालित जनपद व गैर जनपद की विभिन्न चीनीमिलो के किसी न किसी गन्ना क्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण करके सम्बंधित चीनीमिल के अधिकारियो को गन्ना क्रय केन्द्रो पर व्यवस्थाए चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश देते है इतना ही नही प्रदेश के मुखिया सी एम योगी आदित्य नाथ प्रदेश मे सीतलहरी चलने की बात कहते हुए रैन बसेरा मे जरूरतमंद लोगो को भोजन व कम्बल वितरण करते नजर आ रहे है और जनपद सीतापुर के जन

प्रतिनिध,सांसद, विधायक, समाज सेवी,व प्रशासनिक अधिकारी गरीब असहाय जरूरतमंद लोगो को ठण्ड से बचाव के लिए कम्बल वितरण कर रहे है लेकिन जिन किसानो के बल पर चीनीमिल का संचालन होता है उन गन्ना किसानो के लिए रामगढ चीनीमिल मैनेजमेंट द्वारा गन्ना क्रय केंद्रो पर ठण्ड से बचाव के लिए आलाहु का कोई प्रबन्ध नही है और भीषण कोहरा और ठण्ड से किसान कराह रहा है जब इस सम्बन्ध मे सचिव सहकारी गन्ना विकास समित कमलापुर माधव राम से बात की गई तो उन्होंने बताया बहुत जल्द तीनो गन्ना क्रय केन्द्रो पर किसानो के लिए अलाहु का प्रबन्ध करवाया जाएगा,

सूफिया तनवीर का चमकदार आगाजः 'ना तेलुगोडु' से दक्षिण सिनेमा में नई पहचान

सूफिया तनवीर का दमदार डेब्यू तेलुगु फिल्म ह्लना तेलुगोडुह्व के साथ दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ड्रीम टीम प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 12 दिसम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही लोगों से खूब सराहना बटोर रही है। कथा की पकड़, प्रभावशाली निर्देशन और सशक्त प्रस्तुति के बीच जिस कलाकार ने सबसे अधिक ध्यान खींचा है, वह हैं मुंबई की उभरती हुई अभिनेत्री सूफिया तनवीर, जिन्होंने इस फिल्म से दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपना बेहद प्रभावी आगाज किया है।

फिल्म में सूफिया तनवीर मुख्य भूमिका में हरनाथ पोलिचेर्ला के साथ दिखाई देती हैं। इसके अलावा जरीना वहाब, रघु बाबू, नायरा पॉल और अन्य अनुभवी कलाकारों ने भी अपनी उत्कृष्ट अदाकारी से फिल्म को

मजबूती प्रदान की है। कलाकारों के चयन की अहम जिम्मेदारी दीपक बलदेव ठाकुर (ग्लिटर फिल्म अकादमी) ने निभाई, जिन्होंने सूफिया को इस फिल्म से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके दक्षिण फिल्म जगत में कदम रखने का मार्ग प्रशस्त किया।

सूफिया तनवीर की अभिनय यात्रा रंगमंच से शुरू हुई थी। उन्होंने मुंबई में प्रशांत श्रीवास्तव की अभिनय अकादमी से प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल को तराशा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने मुंबई के मंच पर कई प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुतियाँ कीं, जहाँ उनके सशक्त अभिनय ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। रंगमंच से मिली यह गहराई और मजबूती कैमरे के सामने भी झलकती है, जिसने उनके पहली फिल्म के प्रदर्शन को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है।

फिल्म देखने वाले शुरूआती दर्शकों ने सूफिया की सहज अभिव्यक्ति, स्क्रीन पर उनकी स्वाभाविक मौजूदगी और आत्मविश्वास से भरी अदाकारी की खुलकर तारीफ की है। कहानी के भावों को सरलता से पकड़ कर उन्हें दर्शकों तक पहुँचाने की उनकी क्षमता ने उनके अभिनय को और खास बना दिया है। पहली ही फिल्म में इतना प्रभाव छोड़ पाना उनकी प्रतिभा और निरंतर मेहनत का प्रमाण है।